बट्टे खाते डालने के हक में नहीं है, क्योंकि इसके कारण ग्रामीण ऋण प्रणाली को हानि होती है। तथापि, भारतयी रिजर्व बैंक ने अगस्त, 1984 में बाढ़, सूखा, चक्रवात आदि जैसी प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित लोगों को राहत तथा पुनर्वास उपलब्ध कराने के लिए स्थायी निर्देश जारी किए थे। इन निर्देशों में अन्य बातों के साथ-साथ यह परिकल्पना की गई है कि:—

(i) अल्पावधि के उत्पादन ऋणों का मध्यावधिक ऋणों में परिवर्तन किया जाए।

(ii) वर्तमान सावधि ऋण की किश्तों का पुनर्निर्धारण/स्थगित करना, और

(iii) आवश्यकता पर आधारित अतिरिक्त फसल/निवेश, ऋणों आदि को उपलब्ध कराना।

उत्तर प्रदेश में औद्योगिक घरानों को स्वीकृत ऋण

4556. **श्री ईश दत्त यादव:** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत दो वर्षों के दौरान, वर्ष-वार, राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा उत्तर प्रदेश के बड़े औद्योगिक घरानों के लिए कितना ऋण स्वीकृत किया गया है;

(ख) क्या स्वीकृत राशि निर्धारित नियमों के अंतर्गत दी गई है; और

(ग) उत्तर प्रदेश में ऐसे औद्योगिक घरानों पर राष्ट्रीयकृत बैंकों की कितनी राशि बकाया है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह): (क) से (ग) सरकारी क्षेत्र के बैंक उत्पादक उद्यमों को अपने साधारण बैंकिंग कारोबार के एक भाग के रूप में, उन की आवश्यकता पर आधारित ऋणों की जरूरतों का अनुमान लगाने के पश्चात् तथा भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा समय-समय पर जारी मार्ग निर्देशों को ध्यान में रखते हुए अग्रिम स्वीकृत करते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि औद्योगिक इकाइयों के आकार के अनुसार बैंकों द्वारा स्वीकृत ऋणों की धनराशि के बारे में सूचना, उनकी डाटा रिपोर्टिंग प्रणाली से प्राप्त नहीं होती है। तथापि, जून 1988, (अद्यतन उपलब्ध) की स्थिति के अनुसार उत्तर प्रदेश में अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों द्वारा उद्योगों को स्वीकृत ऋण सीमा और बकाया ऋण निम्नानुसार हैं:—

(करोड़ रुपए)

वर्ष	ऋण सीमाएं	बकाया धनराशि
जून, 1988	2588	2016
जून, 1989	3088	2511

Cut in Staff and granting of extension in various Ministries

4557. SHRI KAMKAL MORARKA: Will the Minister of FINANCE be pleased to state:

(a) whether the Ministry of Finance has issued instructions to various Ministries /Departments especially Industry Ministry to cut the staff strength to effect economy in expenditure;

(b) if so, the details thereof and whether the axe is to fall on lower staff;

(c) whether Government have reviewed the policy of granting extension/re-employment of Class-I Officers in various Ministries; and

(d) how many officers (Class-I) are on extension in various Ministries?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI SHANTARAM POTDUKHE): (a) and (b) All the Ministries/Departments of the Government of India (including Ministry of Industry) have been asked to conduct a review and identify posts at different levels that could be considered for surrender/abolition.

(c) No, Sir.

(d) The information is not centrally maintained.

"म्यूचुअल फण्ड" के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश में प्राप्त राशि

4558. **श्री ईश दत्त यादव:** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान उत्तर प्रदेश में "म्यूचुअल फण्ड स्कीम" के अन्तर्गत राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा कितनी राशि एकत्र की गई और इस तरह प्राप्त राशि के कितने प्रतिशत का उत्तर प्रदेश में निवेश किया गया; और

(ख) उत्तर प्रदेश में एकत्र राशि की तुलना में वहां कम राशि का निवेश करने पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है और सरकार इस संबंध में तुरन्त क्या कदम उठाने का विचार रखती है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामेश्वर ठाकुर): (क) और (ख) राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा प्रायोजित म्यूचुअल फण्डों द्वारा एकत्र की गयी राशि पिछले तीन वर्षों के दौरान लगभग 4655.5 करोड़ रुपए थी। म्यूचुअल फण्डों द्वारा जुटाए गए संसाधनों को पूंजी बाजार प्रतिभूतियों जैसे शेयरों और ऋण पत्रों एवं मुद्रा बाजार प्रपत्रों में निवेश किया जाता है। इनमें से अधिकांश प्रपत्र किसी राज्य विशेष से संबद्ध नहीं है, इसलिए उत्तर प्रदेश में किए गए निवेश के संबंध में ब्यौरा नहीं दिया जा सकता।

Credit extended by Punjab & Sind Bank on behalf of U.K. Paint Industries

4559. SHRI VIREN J. SHAH:
SHRI PRAMOD MAHAJAN:

Will the Minister of FINANCE be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the Punjab & Sind Banks has extended very large credits on behalf of UK Paint industries by opening letters of credit worth about by Rs. 67 crores as reported in the Economic Times of 1st February, 1992;

(b) if so, what are the detail in this regard;

(c) whether it is also a fact that the Punjab & Sind Bank in an unprecedented development has failed to honour a Rs. 1.80 crore letter of credit opened by it on account of UK Paint Industries in favour of Oswal Agro Mills Limited;

(d) if so, what are the reasons therefor; and

(e) what action Government have taken in the matter as it adversely affects th Bank's credibility?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI DALBIR SINGH): (a) to (e) In accordance with the provisions of the statutes governing public sector banks, and practices and usages customary among bankers, the banks do not divuge information relating to their individual constituents.

Monitoring of Austerity measures

4560. SHRI MENTAY PADMANABHAM: Will the Minister of FINANCE be pleased to state:

(a) whether government's attention has been invited to newsitem captioned "PM's austerity call falls on deaf ears" in 'Times of India' of the 3rd January, 1992;

(b) if so, what is the monitoring machines in place to supervise austerity measures;

(c) whether any action has been taken to penalise agencies of Ministries or departments or any other arm of Government which are not implementing austerity measures;

(d) the steps being taken to curb unproductive expenditure;

(e) whether it is a fact that lavish functions and ceremonies under Government auspices continue; and

(f) what measures are being proposed to implement austerity measures sincerely?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI SHANTARAM POTDUKHE): (a) Yes, Sir.

(b) and (c) Instructions already exist that officials while not on tour are not permitted to use Staff Cars belonging to Public sector Undertakings/Autonomous organisations etc. It is the duty of every administrative authority to ensure that the officers/staff working under them strictly observe the rules/instructions and that suitable corrective action is taken against erring officials.

Information in respect of the appointments mentioned in the News Item is being collected and will be laid on the Table of the House in due course.

(d) to (f) Every Ministry/Department is expected to make effort to effect utmost economy in expenditure and to ensure that there is no wasteful expenditure. Instructions already exist to effect economy on items like gasolene, telephones, electricity, holding of seminars/conferences, entertainment, travel, purchase of vehicles, etc.